कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को हुडको से बड़ी मदद

गग्गल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए आवास एवं शहरी विकास निगम देगा फंड

पर्यटन बढ़ाने को कांगड़ा एयरपोर्ट को नई उड़ान

हुडको ने 3000 करोड़ रुपये की फंडिंग को मंजूरी दी

कांगड़ा, 23 नवंबर. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित गग्गल हवाई अड्डा अब बड़े पैमाने पर विस्तार की तैयारी में है और इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को बड़ा वित्तीय सहारा मिल गया है.

आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) ने इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए 3000 करोड़ रुपये देने पर सहमति जता दी है, जिससे राज्य सरकार की वर्षों पुरानी योजना को मजबूत गति मिल सकती है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही इस एयरपोर्ट विस्तार को कांगड़ा घाटी के पर्यटन और कनेक्टिविटी को नई दिशा देने वाला प्रोजेक्ट करार दे चुके हैं.

राज्य सरकार अब तक जमीन अधिग्रहण पर खुद ही 600 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है, और भूमि अधिग्रहण की कुल लागत करीब 3000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. केंद्र सरकार से अब तक इस दिशा में कोई वित्तीय सहायता न मिलने के बावजूद, हिमाचल सरकार अपने दम पर इस परियोजना को आगे बढ़ा रही है. अब जबकि हुडको ने फंडिंग को मंजूरी दे दी है, कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार न केवल पर्यटन बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए भी एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की लागत 6300 करोड़ रुपये बताई गई है, और एएआई की अंतिम स्वीकृति अभी शेष है.

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित गग्गल हवाई अड्डे का विस्तार लंबे समय से चर्चा में था, और अब इस परियोजना को मजबूत वित्तीय आधार मिल गया है.

> राज्य सरकार अब तक भूमि अधिग्रहण पर 600 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है, और अनुमान है कि कुल भूमि अधिग्रहण लागत लगभग 3000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. खास बात यह है कि केंद्र सरकार से अभी तक इस दिशा में कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिला है, इसलिए पूरा खर्च फिलहाल हिमाचल सरकार स्वयं वहन कर रही है. एयरपोर्ट के विस्तार संबंधी डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) का मसौदा तैयार करते समय कुल लागत 6300 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहले कुछ तकनीकी और संरचनात्मक आपत्तियाँ दर्ज की थीं, जिन पर डीपीआर तैयार करने वाली एजेंसी और जिला प्रशासन ने विस्तार से प्रतिक्रिया दी है.

24 कैरेट गोल्ड 1,648 रुपये सस्ता, चांदी में 8,000 गिरावट

नई दिल्ली, 23 नवबंर. सोना और चांदी के दामों में इस साल लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. जहां पिछले कुछ महीनों में इनकी कीमतों में तेजी आई थी, वहीं हाल के दिनों में इसका असर उल्टा देखने को मिला. बीते हफ्ते चांदी की कीमतों में 8,238 प्रति किलो तक की बड़ी गिरावट हुई, जबकि 24 कैरेट सोने का भाव 1,648 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया. घरेलू बाजार के आंकड़े बताते हैं कि 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाले सोने के वायदा भाव में 8,009 रुपये की कमी दर्ज की गई. घरेलू बाजार में भी 14 नवंबर से 21 नवंबर के बीच सोने के दाम लगातार नीचे आए. अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का बंद भाव 1,23,146 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

इजराइल कृषि मंत्री से मिले गोयल द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति

नयी दिल्ली, 23 नवंबर (वार्ता) केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने इजरायल दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को यहूदी राष्ट्र के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री एवी डिचर से मुलाकात की जिसमें दोनों देश खेती-बाड़ी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए.

श्री गोयल और श्री डिचर की बैठक के दौरान कृषि क्षेत्र में आपसी सहयोग की स्थित और उसके भविष्य पर विस्तार से चर्चा की गयी. श्री डिचर ने इज़राइल के 25 साल के खाद्य सुरक्षा रोडमैप, आधुनिक बीज-वर्धन रणनीति और कृषि के लिए पानी के पुन: उपयोग की प्रौद्योगिकी में देश की अग्रणी स्थिति के बारे में जानकारी दी. श्री गोयल पेरेस सेंटर फ़ॉर पीस एंड इनोवेशन भी गये जहां उन्हें इजराइल के अग्रणी प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी के बारे में बताया गया. उन्होंने वहां ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्टेंट प्रौद्योगिकी और आयरन डोम प्रणाली सहित कई महत्वपूर्ण नवाचार देखे. साथ ही, भविष्य की प्रौद्योगिकी और इमर्सिव वर्चुअल-रियलिटी समाधानों से भी रू-ब-रू हुए. उन्होंने पेरेस सेंटर को एक प्रेरणा देने वाला संस्थान बताया जो इजराइल की रचनात्मकता, नवाचार और सामाजिक प्रभाव की यात्रा को दिखाता है. केंद्रीय मंत्री किबुत्ज़ रमत राचेल भी गये जहां उन्होंने को-ऑपरेटिव लिविंग, टिकाऊ कृषि पद्धति और समुदाय आधारित नवाचार के इसके मॉडल को देखा. इन सबके जरिये श्री गोयल ने इजराइल की प्रौद्योगिकी ताकत और ग्रामीण एवं सतत विकास के प्रति उनकी सोच के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली. अपनी यात्रा के पहले दिन 20 नवंबर को श्री गोयल ने इजरायल के आर्थिक मामलों के मंत्री नीर बरकत से मुलाकात की थी. दोनों नेता मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए और वार्ता प्रक्रिया के निर्देशन के लिए टर्म्स ऑफ रिफ्रेंस समझौते पर हस्ताक्षर किये.

व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की बैठकें

दोनों नेताओं ने विभिन्न इजराइली कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात की. उन्होंने इजराइली मीडिया से संवाद किया और हीरा व्यापारियों से मुलाकात की. उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में हीरे का व्यापार काफी महत्व रखता है. वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया है कि श्री गोयल ने इस यात्रा के दौरान कृषि, प्रौद्योगिकी, नवाचार और व्यापार में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए कई बैठकें कीं.

इस्पात उद्योग को मिली राहत

55 आईएस मानकों का प्रवर्तन टला

नयी दिल्ली, 23 नवंबर. इस्पात उद्योग को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 55 आईएस (इंडियन स्टैंडर्ड) मानकों का प्रवर्तन एक से तीन साल के लिए निलंबित कर दिया है.

इस्पात मंत्रालय ने शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि संभावित डाउनस्ट्रीम मूल्य निर्धारण प्रभावों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा उपभोक्ता उद्योगों के लिए इस्पात की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता और कुछ विशेष ग्रेड के लिए आयात पर निरंतर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए गैर-वित्तीय नियामक सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला किया है.

समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम, छोटे इस्पात उत्पादकों के लिए समर्थन और घरेलू आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने से संबंधित विचारों का भी आकलन किया. मंत्रालय ने इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 जारी किया है जिसका मकसद इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 में संशोधन करना है.

विज्ञप्ति के अनुसार, इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 की अनुसूची 1 में कुल 42 आईएस मानकों का प्रवर्तन तीन साल के लिए निलंबित किया गया है. इसमें मुख्य रूप से इंजीनियर्ड उत्पादों, ऑटोमोटिव और टिकाऊ वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किये जाने वाले इस्पात ग्रेड शामिल हैं.

> वहीं, इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 की अनुसूची 1 में शामिल अन्य 13 आईएस मानकों को लागू करना एक साल के लिए टाला गया है. इसमें मुख्य रूप से विशिष्ट और उच्च-शुद्धता की जरूरत वाले ऐप्लिकेशनों में उपयोग किये जाने वाले विशिष्ट इस्पात ग्रेड शामिल हैं, जिनमें असाधारण शक्ति, कठोरता, आयामी सटीकता और तापीय स्थिरता की आवश्यकता वाली सामग्रियां शामिल हैं.

गेहूं, चीनी में साप्ताहिक गिरावट

नयी दिल्ली, 23 नवंबर. घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव स्थिर रहे. गेहूं और चीनी के दाम घट गये जबकि दालों में तेजी देखी गयी. खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा. घरेलू थोक जिंस बाजारों में सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत लगभग स्थिर रही और सप्ताहांत पर यह 3,819.66 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा. गेहूं नौ रुपये की टूटकर 2,848.14 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया. आटे की कीमत 11 रुपये फिसलकर 3,301.38 रुपये प्रति क्विंटल हो गयी. बीते सप्ताह सरसों तेल 44 रुपये प्रति क्विंटल सस्ता हुआ जबकि सूरजमुखी तेल और पाम ऑयल में टिकाव रहकर मजबूत रहा. मूंगफली तेल औसतन 60 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हुआ.

रेशों से कपड़ा क्षेत्र में आएगी क्रांति : गिरिराज

केंद्रीय मंत्री ने की आक पर निट्रा के अग्रणी अनुसंधान की प्रशंसा

निट्रा ने इस तकनीक को कई प्रमुख कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया

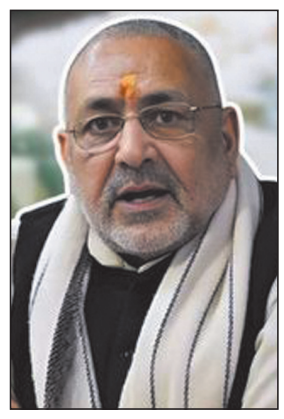

नयी दिल्ली, 23 नवंबर. केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को कहा कि आक (मिल्कवीड) से बने रेशों में कपड़ा क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता है.

श्री सिंह ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में उत्तर भारतीय वस्त्र अनुसंधान संघ (निट्रा) के दौरे पर संस्थान के परिसर में उगायी जा रही आक की फसल का निरीक्षण किया. केंद्रीय मंत्री ने आक पर निट्रा के अग्रणी अनुसंधान की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसमें कपड़ा क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता है. यह आधुनिक युग के रेशों में से एक है.

उन्होंने कहा कि निट्रा ने इस तकनीक को पहले ही कई प्रमुख कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया है और इसे अपनाने के लिए अन्य कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है.

केंद्रीय मंत्री ने निट्रा में स्थापित देश की पहली मैनिकिन फ्लेम टेस्ट प्रणाली को औपचारिक रूप से राष्ट्र और उद्योग जगत को समर्पित किया.

> श्री सिंह ने नव स्थापित इस प्रणाली के बारे में कहा कि इससे न केवल कपड़ा उद्योग, बल्कि इस्पात, तेल, गैस, पेट्रोलियम, रेलवे और रसायन क्षेत्र को भी लाभ होगा. यह परीक्षण प्रणाली उच्च जोखिम वाले वातावरण में कामगारों के जीवन की रक्षा करने में मदद करेगी. निट्रा के महानिदेशक डॉ. एम.एस. परमार ने कहा कि यह तकनीक सुरक्षात्मक कपड़ों के महत्व को मजबूत करती है और विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक कपड़ा के सटीक प्रकार को निर्धारित करने में मदद करती है.

एफपीआई ने नवंबर में किया 3,504 करोड़ का निवेश

मुंबई, 23 नवंबर. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने नवंबर में अबतक भारतीय पूंजी बाजार में 3,504 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया है.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में एफपीआई इक्विटी बाजार में शुद्ध रूप से बिकवाल रहे जबकि डेट, हाइब्रिड इनस्ट्रूमेंट और म्यूचुअल फंडों में उनका निवेश सकारात्मक रहा है. उन्होंने इक्विटी से इस महीने 3,788 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की. डेट में उनका शुद्ध निवेश 4,467 करोड़ रुपये और म्यूचुअल फंड में 2,713.33 करोड़ रुपये रहा है.

हाइब्रिड इनस्ट्रूमेंट्स में भी एफपीआई ने 112.16 करोड़ रुपये का निवेश किया है. यह लगातार दूसरा महीना है जब एफपीआई भारतीय पूंजी बाजार में सकारात्मक बने हुए हैं. अक्टूबर में उन्होंने 35,246 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था जबकि जून से सितंबर तक चार महीने लगातार बिकवाल रहे थे.

पुरानी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हुआ महंगा

नई दिल्ली, 23 नवंबर. पुरानी गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट की फीस अब कई गुना बढ़ गई है. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत 20 साल पुरानी कार का फिटनेस टेस्ट अब 15,000, बाइक का 2,000 और हैवी कमर्शियल वाहन का 25,000 हो गया है. इसके साथ ही फिटनेस सर्टिफिकेट 15 साल की बजाय अब 10 साल में अनिवार्य कर दिया गया है. नई व्यवस्था में गाड़ियों को उम्र के आधार पर तीन कैटेगिरी में बांटा गया है- 10-15 साल, 15-20 साल और 20 साल से अधिक.

सात कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बढ़ा

इंफोसिस का 17,490 करोड़ रुपये बढ़ा

एचडीएफसी बैंक का 15,35,133 करोड़ रुपये बढ़ा

मुंबई, 23 नवंबर. घरेलू शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह प्रमुख सूचकांकों में रही तेजी के कारण बीएसई की शीर्ष 10 में से सात कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1,28,282 करोड़ रुपये बढ़ गया जबकि अन्य तीन का 14,015 करोड़ रुपये घट गया.

विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण (एमकैप) सप्ताह के दौरान 36,673 करोड़ रुपये बढ़ा. दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल का एमकैप 36,579 करोड़ रुपये और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की इंफोसिस का 17,490 करोड़ रुपये बढ़ा. सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस का एमकैप भी 16,299 करोड़ रुपये और एचडीएफसी बैंक का 14,608 करोड़ रुपये बढ़ गया. भारतीय स्टेट बैंक के बाजार पूंजीकरण में 4,846 करोड़ रुपये और एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनीलिवर में 1,786 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई.

समाचार विशेष

महाविकास अघाड़ी में दरार गहरी!

भाजपा को मिल सकता है फायदा

मुंबई. महाराष्ट्र में महायुती सरकार अपने अंदरूनी मतभेदों को सुलझाने में लगी है, लेकिन असल में राजनीतिक बढ़त बीजेपी को विपक्षी खेमे की उथल-पुथल से मिलती दिख रही है. महा विकास आघाड़ी (एमवीए) में इन दिनों माहौल गर्म है.

कांग्रेस का अकेले बीएमसी चुनाव लड़ने का फैसला शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरद पवार गुट) के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है. विपक्ष की यह टूट बीजेपी के लिए सीधा लाभ बनकर सामने आ रही है.

कांग्रेस ने हाई-स्टेक्स बीएमसी चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान किया है. पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा है कि मुंबई कांग्रेस की यही इच्छा थी और हाईकमान ने इसे मंजूरी दे दी. लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग के बावजूद, स्थानीय इकाइयाँ अकेले मैदान में उतरना चाहती हैं. यह फैसला स्पष्ट संकेत देता है कि एमवीए के भीतर रणनीति और नेतृत्व को लेकर असहमति बढ़ती जा रही है.

बीएमसी चुनाव में यह कदम विपक्षी एकता को कमजोर करता है, और बीजेपी के लिए मैदान और भी खुला हो जाता है.

कई सालों बाद ठाकरे परिवार के अलग-अलग गुट - उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की मनसे एक-दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं. हाल ही में एमवीए नेताओं ने एमएनएस के साथ मिलकर मतदाता सूची गड़बड़ी के खिलाफ रैली भी की, जिस पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सवाल उठाए. इससे एमवीए में असंतोष और बढ़ गया है.

बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा

हाल ही में बिहार में शानदार जीत से बीजेपी का मनोबल पहले ही ऊंचा है. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, ताजा सर्वे बताते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी का समर्थन पिछली बार से ज्यादा है. स्थानीय निकाय चुनावों में यह रुझान पार्टी के लिए बड़ा सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. देवेंद्र फडणवीस ने तो यह भी कहा कि अगर विपक्ष बीएमसी चुनाव साथ मिलकर भी लड़ लेता, तब भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता. एमवीए में बढ़ते विवाद, कांग्रेस का अलग लड़ना, ठाकरे भाइयों की संभावित नजदीकी और बीजेपी का मजबूत चुनावी नेटवर्क इन सारी परिस्थितियों से साफ है कि स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिलता दिख रहा है.

हार की ईमानदार समीक्षा नहीं

पटना. विधानसभा चुनाव के नतीजों के तीन दिन बाद राष्ट्रीय जनता दल ने हार की समीक्षा की. सभी हारे हुए उम्मीदवारों को पटना बुलाया गया और उनसे बात की गई. जीते विधायकों के साथ भी समीक्षा हो रही है.

इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी समीक्षा कर रही है. लेकिन उससे पहले राजद की समीक्षा से अंदाजा हो गया है कि कोई ईमानदार बातचीत नहीं होने वाली है. सभी उम्मीदवारों ने समझ लिया है कि पार्टी के नेता क्या सुनना चाहते हैं. वे उसी हिसाब से हार के कारण बता रहे हैं. असल में चुनाव नतीजों के बाद राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाल कर लंबी चौड़ी समीक्षा की है. उन्होंने जो लिखा है उसका लब्बोलुआब है कि दुनिया में कहीं भी 90 फीसदी स्ट्राइक रेट नहीं होती है और इसको सही नहीं माना जा सकता है. उधर राहुल गांधी ने खुद ही कह दिया है कि चुनाव पहले दिन से निष्पक्ष नहीं था.

तभी महागठबंधन की दोनों बड़ी पार्टियों राजद और कांग्रेस के नेता चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं. हर उम्मीदवार के पास किसी न किसी किस्म की गड़बड़ी के कथित सबूत हैं.

अमरावती संभाग की सात नगरपालिका पर संकट

मुंबई. अमरावती संभाग में दर्यापुर, चिखलदरा नगर पालिका और धारणी नगर पंचायत सहित सात स्थानीय निकायों के चुनाव संकट में पड़ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होने की स्पष्ट चेतावनी के बीच इन स्थानों पर आरक्षण प्रतिशत बढ़ने की चर्चा है, जिससे चुनाव रद्द होने की संभावना बन गई है.

राज्य में नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव प्रक्रिया जारी है और 2 दिसंबर को मतदान होना है. लेकिन अमरावती संभाग की सात नगर परिषदों/नगर पंचायतों का भविष्य अधर में है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जहां आरक्षण 50 प्रतिशत से ज़्यादा हो गया है, वहां चुनाव रद्द किए जा सकते हैं. इस सूची में अमरावती जिले की दर्यापुर व चिखलदरा नगर परिषदें और धारणी नगर पंचायत, यवतमाल जिले की तीन नगर परिषदें तथा वाशिम जिले की एक नगर परिषद शामिल हैं.

आरक्षण का आंकड़ा 50 फीसदी से अधिक- दर्यापुर नगर परिषद में ओबीसी का प्रतिशत 6.75 मानकर 7 सीटें आरक्षित की गईं, जिससे कुल आरक्षण 64.71 प्रतिशत हो गया. चिखलदरा नगर परिषद में एसटी आरक्षण सीधे 75 प्रतिशत तक पहुंच गया है. पिछले चुनाव में एसटी के लिए 3 सीटें थीं, इस बार बढ़ाकर 7 कर दी गई हैं. ओबीसी सीटें 4 से 5 और एससी सीटें 2 से 3 कर दी गई हैं. धारणी नगर पंचायत में 4.59 प्रतिशत आधार पर ओबीसी के लिए 5 सीटें आरक्षित कर कुल आरक्षण 64.71 प्रतिशत हो गया. प्रशासन का कहना है कि आरक्षण निर्धारण राज्य सरकार की 8 जुलाई 2025 की अधिसूचना के आधार पर किया गया है. अधिसूचना के बिंदु 2 के अनुसार, आरक्षण तय करते समय 0.5 या उससे अधिक अंश को 1 माना जाएगा, जबकि 0.5 से कम को अनदेखा किया जाएगा. 1965 एक्ट के सेक्शन 3(2)(अ) के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित की गईं, लेकिन इससे कई जगहों पर आरक्षण संवैधानिक सीमा से ऊपर चला गया.

सरकार और प्रशासन को बड़ा झटका

इन आंकड़ों के सामने आने के बाद सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट भूमिका को देखते हुए इन सात स्थानों के चुनाव रद्द होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. नगर पालिका प्रशासन सहआयुक्त विकास खंडारे ने कहा कि यह विषय न्यायालयीन प्रक्रिया में है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना संभव नहीं है. राज्य चुनाव आयोग से अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं. वर्तमान में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के तहत मिले निर्देशों पर अमल किया जा रहा है. आयोग की ओर से जो भी नए निर्देश मिलेंगे, उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

विशेष | नागपुर में 90 फीसदी सीटों पर सीधी भिड़ंत

जहां दोस्ती, वहीं जंग! बिखर गए गठबंधन

नागपुर. स्थानीय निकाय चुनावी रण में खुद को एक दूसरे का मित्र बताने वाले दल अब आपस में ही भिड़ने वाले हैं. फिर चाहे वह भाजपानीत महायुति हो या कांग्रेसनीत मविआ. कुछ सीटों को छोड़ दें तो नगर परिषद व नगर पंचायत चुनाव में 90 फीसदी सीटों पर सभी ने अपने-अपने स्वतंत्र उम्मीदवार उतार दिये हैं.

बड़ी पार्टियों के साथ हमेशा खड़े रहे छोटे दल उनके अड़ियल रवैये के चलते अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मैदान पर उन्हें चुनौती देते नजर आ रहे हैं. महायुति में भाजपा ने जिले की सभी 27 नप-नपं अध्यक्ष पदों के साथ ही सदस्यों को मैदान पर उतार दिया है तो सरकार में शामिल शिंदे सेना ने 15 और राकां अजित पवार गट ने भी 15 नगराध्यक्षों के साथ सदस्य मैदान में उतार दिए हैं. तीनों दलों के उम्मीदवार एक दूसरे से भिड़ेंगे. वहीं कांग्रेस ने 23 नगराध्यक्ष उतारे हैं. 1 सीट पर गठबंधन किया है और राकां शरद पवार की वजनदारी वाली 3 सीट छोड़ दी है. मविआ में शामिल राकां शरद पवार पार्टी ने 11 नप-नपं में अध्यक्ष उम्मीदवार दिये हैं. वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी 11 सीटों पर अध्यक्ष के उम्मीदवार सहित अपना स्वतंत्र पैनल उतारा है.

भाजपा की प्रतिष्ठा पर मित्र करेंगे वार- भाजपा नेताओं की ओर से अंत तक यही कहा जाता रहा कि निकाय चुनाव महायुति एक साथ लड़ेगी. लेकिन उसने मित्र दलों को सकारात्मक जवाब नहीं दिया और अपने प्रभाव वाली 15 सीटों पर राज्य मंत्री आशीष जायसवाल, कृपाल तुमाने ने अपने स्वतंत्र उम्मीदवार उतार दिये. वहीं 15 सीटों पर राकां अजित पवार गुट ने भी बिगुल फूंक दिया है. भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और जिले में उसके 6 में से 5 विधायक हैं. वजनदार मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जा रहा है. वे पूरे राज्य के चुनाव प्रभारी हैं और अपने गृह जिले में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है. गठबंधन नहीं होने के चलते इस चुनाव में लगभग सभी सीटों पर मित्र दल ही उनकी प्रतिष्ठा में पलीता लगाने का प्रयास करेंगे.

रामटेक और कामठी हॉट सीटें

रामटेक में शिंदे सेना ने भी भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा है. वहीं कांग्रेस इस बार अपने निष्ठावान कार्यकर्ता दामोदर धोपटे को साइट कर प्रहार जनशक्ति पार्टी के रमेश कारेमोरे को टिकट दी. धोपटे ने निर्दलीय नामांकन दर्ज किया है. अगर वे अपना नाम वापस नहीं लेते तो निश्चित रूप से कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के वोट कांटेंगे. इससे रामटेक में सीधी टक्कर 2 मित्र दलों भाजपा व शिंदे सेना के बीच ही होगी. यह सीट राज्य मंत्री जायसवाल की है इसलिए हॉट बन गई है. कामठी राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के लिए चुनौतीभरी हो गई है. गठबंधन नहीं होने और बीजेपी के रवैये से नाराज होकर बरिएमं की सुलेखा कुंभारे ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है. इस सीट में उनका खासा प्रभाव है और भाजपा उम्मीदवार को भारी नुकसान पहुंच सकता है. यहां से कांग्रेस, राकां अजित पवार गुट, शिंदे सेना, उद्धव सेना, आम आदमी पार्टी, एमआईएम, बसपा के साथ ही वंचित तक ने अपने-अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं. कौन किसके वोट काटेगा, यह गणित अब समझ से परे हो गया है.